Budget Announcements 2019-20

Panchayati Raj Department

Sr. No.	File Number	Annoucement Para /Description	Budgetary Requirement as per Department (In Lakhs)	Action Taken by Dept.	Status
1	BAM19PRD1341500	134.15.0(2019-2020 (Modified Budget)) (10/07/2019) प्रदेश में इस वर्ष ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा 5160 पदों पर भर्तियां की जायेंगी।	No Funds Required for Implementation	विकास अधिकारी के 47 पदो हेतु अभ्यर्थना कार्मिक विभाग प्रेषित, जिसकी भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा की जावेगी। कनिष्ठ अभियन्ता के 2100 व लेखा सहायक के 900 पद वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2017 से ही Kept in Abyence रखे हुए है। वित्त विभाग द्वारा इनका कार्यात्मक औचित्य एवं व्यय नरेगा के प्रशासनिक मद से किया जा सकता है या नहीं के बारे मे जानकारी चाहने पर नरेगा द्वारा अवगत कराया कि उनके प्रशासनिक मद में राशि उपलब्ध नही है। पत्रावली वित्त विभाग में प्रक्रियाधीन है। राज्य की जिला परिषदों के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारियों के रिक्त 2140 पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग एवं कार्मिक विभाग से सहमति प्राप्त हो चुकी है। कार्मिक विभाग द्वारा आरक्षण के संबंध में दिनांक 16.01.2020 को जारी परिपत्र के क्रम में जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्गवार पदों का मिलान किया जाकर, वर्गवार रिक्तियों के आरक्षण के निर्धारण एवं अनुमोदन हेतु पत्रावली कार्मिक विभाग को दिनांक 31.01.2020 को प्रेषित की गयी है।	Task Initiated

Budget Announcements 2019-20

Sr. No.	File Number	Annoucement Para /Description	Budgetary Requirement as per Department (In Lakhs)	Action Taken by Dept.	Status
2	BAM19PRD1060100	106.01.0(2019-2020 (Modified Budget)) (10/07/2019) प्रदेश के नगरपालिका एवं नगर परिषद् मुख्यालयों को छोड़कर शेष सभी पंचायत समिति मुख्यालयों पर 'अम्बेडकर भवन' बनाया जायेगा।	Budget for the Financial Year Required from FD 2019-20 = 2200.00	कुल 160 पंचायत समितियों मुख्यालयों पर अम्बेडकर भवन बनाये जाने है। एक भवन की अनुमानित लागत 55 लाख रूपये है, तदानुसार 88 करोड रूपये की आवश्यकता होगी। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा प्रारम्भिक कार्यवाही हेतु 2 लाख की राशि प्रति भवन उपलब्ध कराने की सहमति दे दी गई है। भूमि चिन्हिकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है। अब तक 130 में भूमि चिन्हिकरण का कार्य कर लिया गया है।	Task Initiated
3	BAM19PRD1060000	106.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) (10/07/2019) नियोजित विकास में मास्टर प्लान की अहमियत को समझते हुए प्रदेश के गांवों में मास्टर प्लान बनाये जायेंगे, जिसमें भविष्य के लिए क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य, आबादी विस्तार, खेल सुविधायें, पार्क, सरकारी भवनों, सड़क	No Funds Required for Implementation	राजस्व विभाग द्वारा कार्य में राजस्व कार्मिकों द्वारा सहयोग प्रदान करने हेतु दिनांक 18.09.19 व विलेज मास्टर प्लान बनाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश दि 14.10.19 एवं 25.10.19 को जारी कर दिये गये है। भूमि का चिन्हिकरण पटवारियों के सहयोग से करने की समय सीमा निर्धारित कर समस्त संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर को पत्र दि 04.11.19 को विस्तृत समयबद्ध दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। इस हेतु संबंधित ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच, पटवारी, कनिष्ठ अभियन्ता आदि का पंचायत समिति स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किये जा चुके है। वित्त विभाग को प्लान तैयार करने हेतु राज्य मद से राशि 5.00 लाख रूपये की दर से कुल राशि 50.00 करोड उपलब्ध करवाये जाने	Task in Progress

Budget Announcements 2019-20

Sr. No.	File Number	Annoucement Para /Description	Budgetary Requirement as per Department (In Lakhs)	Action Taken by Dept.	Status
		एवं अन्य विकास की आवश्यकताओं का आकलन करके भूमि का चिन्हिकरण पटवारियों के सहयोग से किया जायेगा।		हेतु अनुरोध किया गया था जिसपर वित्त विभाग द्वारा राज्य मद से कोई राशि उपलब्ध नहीं करवाने एवं विलेज मास्टर प्लान के तहत गतिविधियों को विभिन्न योजनाओं से क्रियान्वित करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। प्लान बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राज्य के कुल 46106 गांवों में से 41124 गांवों में विकासात्मक गतिविधियों के अन्तराल का पता लगाने एवं भूमि का चिन्हिकरण करने का सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है।	
4	BAM19WSD2600000	260.0.0(2019-2020 (Modified Budget)) (Hon'ble CM Reply on 16/07/2019) डूंगरपुर जिले की तीन नदियों (मोरन, वातरक व भादर) के संयुक्त क्षेत्र में वाटरशेड परियोजना के तहत् भूमि व जल सरंक्षण कार्य किये जायेंगे।	Budget for the Financial Year Required from FD 2019-20 = 50.00	डूंगरपुर जिले की तीन नदियों यथा मोरन, वातरक व भादर के कैचमेन्ट का क्षेत्रफल चिन्हित कर लिया गया है, जिसका कैचमेन्ट क्षेत्रफल 1.295 लाख हैक्टेयर है। 57544 हैक्टेयर की परियोजना तैयार कर राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन कराया जा चुका है। कुल 100 करोड की परियोजना मे से वर्ष 2019 –20 में 0.50 करोड व्यय किये जावेगे। आयोजना विभाग द्वारा दिनांक 18.02.2020 को पत्रावली पर सैद्धांतिक सहमति देने के पश्चात पत्रावली लेखा शीर्ष खोलने एवं अनुमोदन हेतु वित्त विभाग को भिजवाई जा रही है।	Task Initiated

Budget Announcements 2019-20

Sr. No.	File Number	Annoucement Para /Description	Budgetary Requirement as per Department (In Lakhs)	Action Taken by Dept.	Status
5	BAM19WSD1050100	105.01.0(2019-2020 (Modified Budget)) (10/07/2019) जनता में जल संरक्षण के प्रति जागरुकता लाने, परंपरागत पेयजल स्रोतों को पुनः जीवित करने, नवीन स्रोतों के निर्माण एवं सघन वृक्षारोपण के लिए 'राजीव गांधी जल संचय योजना' प्रारंभ करने की घोषणा।	Budget for the Financial Year Required from FD 2019-20 = 39200.00	The guidelines have been Issued and Rajiv Gandhi Jal Snanchay Yojana Started on 20th August 2019.	**Task Completed**